

पहला कॉलम



दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण और तोमर को जारी किया नोटिस

बरी किए जाने के फैसले को महिला पहलवानों ने दी है चुनौती, अब 9 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली ।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी किया। इस मामले में बृजभूषण को बरी किए जाने के फैसले को महिला पहलवानों ने चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने सोमवार को चार महिला पहलवानों को याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सेशन कोर्ट ने बृजभूषण के साथ डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी नोटिस भेजा। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच यह विवाद 2023 में सामने आया था। कई नामी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि 2016 से 2022 के बीच बृजभूषण की ओर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैम्प, डब्ल्यूएफआई कार्यालय और अन्य स्थानों पर उनके साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर को सह-आरोपी बनाया। महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 3 अगस्त को मामले में दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को बरी कर दिया। चार महिला पहलवानों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 3 अगस्त के आदेश को खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है। याचिका के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के समर्थन वाली पूरी तस्वीर देखने के बजाय छोटी-छोटी और गैर-ज़रूरी गलतियों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हीं के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ पूरे मामले को खारिज कर दिया।

दीपके का 2 अक्टूबर से जेल भरो आंदोलन, चुनौतियों के बावजूद सीईसी पर दबाव जारी

प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक ने किया समर्थन का ऐलान

मुंबई ।

कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आगामी 2 अक्टूबर से मुंबई में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। यह फैसला तब लिया गया जब मुंबई पुलिस ने पार्टी को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर पहले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार किया। दीपके ने नए आंदोलन की जानकारी दी, जो उनकी दृढ़ता और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की उनकी मांग को दिखाता है। मुंबई पुलिस ने सीजेपी को 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में होने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने इसके पीछे उच्च न्यायालय के निर्देश, नगर निकाय की अनुमति का अभाव और संभावित यातायात बाधाओं का हवाला दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मौजूदा आदेशों के तहत पुलिस विभाग को इस प्रतिष्ठित मैदान में सार्वजनिक सभाओं की इजाजत देने का अधिकार नहीं है।सीजेपी लगातार सीईसी ज्ञानेश कुमार पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने और नागरिकों से मतदान का अधिकार छीनने का आरोप लगाती रही है। पार्टी ने पहले ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर आपत्ति जताकर जंर-मंतर 2.0 की चेतावनी दी थी और 48 घंटे के भीतर उनके इस्तीफे की मांग की थी। इसमें विफल रहने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन और दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी गई थी। जेल भरो आंदोलन की घोषणा पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका को असम में हिरासत में लेने के कुछ ही समय बाद की गई, हालांकि उन्हें बाद में रिहा किया गया। इन झटकों के बावजूद, सीजेपी को लड़ाख के प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक का समर्थन मिला है।

आईआईटी छात्र साहिल वाकोडे के पिता का आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन

मुंबई ।

आईआईटी मुंबई के छात्र साहिल वाकोडे के पिता रवींद्र वाकोडे ने अपने बेटे की कथित आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग कर मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन करने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि उनका यह उपवास तब तक जारी रहेगा जब तक उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को उचित सजा नहीं मिलती। रवींद्र वाकोडे ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है, भले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे बेटे को संवैधानिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। यह छत्रपति शिवाजी, फुले, शाहू और आंबेडकर का राज्य है।

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पेमेंट पर मचें'ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है। हालांकि, कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉर्रपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी

किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहनना की पीठ ने अधिवक्ता अंजन दत्ता द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के लिए सहमति जाहिर की और सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी

सीएम रेखा ने ऑनलाइन लाइसेंस, एनओसी के लिए ‘दिल्ली उद्योग मित्र’ पोर्टल शुरू किया

नई दिल्ली ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारोबार सुगमता पहल के तहत विभिन्न प्रकार की मंजूरी और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए सोमवार को ‘दिल्ली उद्योग मित्र’ पोर्टल शुरू किया। सीएम गुप्ता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत ‘दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल’ को शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़े इस पोर्टल पर 21 विभागों की 100 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध होंगी। गुप्ता ने कहा कि उद्यमियों को आवश्यक

अनुमतियों, आवेदन की स्थिति और प्रक्रियाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, + कारोबार सुगमता को जमीन पर उतारते हुए हमारी सरकार दिल्ली को उद्यम और निवेश के लिए और अधिक सुगम बना रही है।+ उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एकल खिड़की पोर्टल व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा और उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को इसके माध्यम से विभिन्न लाइसेंस और एनओसी के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। सिरसा ने कहा कि पोर्टल उद्यमियों और उद्योगपतियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान

है। केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि नए ढांचे के तहत लगभग 96 प्रतिशत लेनदेन शुल्क मुक्त रहने वाले हैं। जबकि रेलवे, दूरसंचार, बीमा और कृषि जैसे आवश्यक सेवाओं के लिए एमडीआर 5 रुपये तक सीमित होगा। अधिवक्ता दत्ता की याचिका आरोप लगाती है कि ये शुल्क पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू गए हैं। याचिका भुगतान और निपटान प्रणाली

अधिनियम, 2007 की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देती है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रावधान कार्यपालिका को बिना स्पष्ट दिशानिर्देशों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क तय करने का अधिकार देता है।

गौरतलब है कि 15 अक्टूबर से लागू हुए नए फेब्रवर्क के तहत, 2,000 रुपये से अधिक के सामान्य पर्सन टू मचेंट (पी2एम) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीईसी के घर पर पोती कालिख,लिखा वोट चोर



करेगा जिसके कारण उन्हें अनुमति के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदक पोर्टल के

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीईसी के घर पर पोती कालिख,लिखा वोट चोर –भड़के नड्डा बोले– जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, इनका भ्रम चूर चूर होगा

नई दिल्ली ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी बवाल खत्म नहीं हो रहा है।

सोमवार को कांग्रेस देशभर में कई शहरों में ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। यूपी के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीईसी के घर के बाहर कालिख पोत दी और वोट चोर लिख दिया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार में जरा भी नैतिकता है, तो उन्हें उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने बेंगलुरु में कहा कि उनके अपने ही लोगों ने उनकी पोल खोल दी है और उनके अपने लोग ही यह बात

कह रहे हैं। यहां तक कि केरल के मुख्य सचिव का भी कहना है कि सीईसी ने खुद उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर है वह बीजेपी की विचारधारा का प्रचार कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमलावर रुख पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जो ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, उन्हें देश ने पहले भी करारा सबक सिखाया है। आगे भी इनका भ्रम चूर चूर होगा। नड्डा ने कहा कि देश के 140 करोड़ों भारतीयों के संकल्प पर देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के हर झूठ की हवा निकल चुकी है।

यह नया परंपंच कर रहे हैं। माहौल खराब करने में लगे हैं।

राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल...सबकी मानसिकता देश की संवैधनिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना है। यह सब सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा इन सबके मंसूबों को नकारा है। आज देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से भारत का डंका बज रहा है। तब इंडी गठबंधन हताश है। चुनाव आयोग से लेकर देश के सर्वोच्च अदालत तक इनके झूठ की हवा निकल चुकी है। तब से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तब ये नए झूठ

फैलाने में लगे हैं। राहुल गांधी बार-बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाते। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल...इन्हें न राष्ट्र की सुरक्षा से सरोकार है न देश के मान सम्मान से। इन्हें सत्ता परिवारवाद के लिए चाहिए। बीजेपी के पलटवार पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को अपना वकील नियुक्त किया है? बीजेपी कौन है? क्या बीजेपी इसमें कोई पक्ष है? बीजेपी एक पक्ष है क्योंकि उन्हें चोरी का परिचारक है, है ना? इसलिए ये लोग उनकी वकालत कर रहे हैं। बता दें, कई महीनों से चल रहे एसआईआर विवाद के बीच 23 सितंबर को एक अखबार की रिपोर्ट से सियासी हंगामा नए सिरे से शुरू हो गया।

दिल्ली में 1 नवंबर से निर्माण कार्य पर रोक

नई दिल्ली ।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 1 नवंबर से राजधानी में निर्माण कार्य और बाहरी तोड़फोड़ के काम पर रोक रहेगी। वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर आज सुबह पर्यावरण भवन में अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदूषण की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील समय में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। 1 नवंबर से बाहरी तोड़फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर रोक शुरू होगी,

जबकि 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर रोक

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद इन गतिविधियों को सीमित करना है जिन्से सर्दियों के महीनों में धूल उड़ सकती है। सरकार ने 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी

2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की भी घोषणा की है।

पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के एक और उपाय के तहत दिल्ली सरकार ने अधिकृत पार्किंग जगहों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया है। बदले हुए पार्किंग शुल्क 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मालिकाना हक और प्रबंधन वाली पार्किंग जगहों को इस फैसले से

बाहर रखा जाएगा। इस कदम का मकसद लोगों को निजी वाहनों के लिए कम करने से रोकना है। सरकारी दफ्तरों में बदले हुए समय का पालन होगा दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तरों के समय में बदलाव की भी घोषणा की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8-30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6-30 बजे तक काम

करेंगे। सरकार ने कहा है कि समय में यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए किए जा रहे उपायों का हिस्सा है। सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों को 50 प्रतिशत वर्क फॉर्म होम (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत, 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कार्यालय से काम करेंगे। यह उपाय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित घर की गेट-दीवार पर लिखा गया ‘गद्दार ज्ञानेश’, पोती कालिख

आगरा ।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित घर के बाहर सोमवार सुबह प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की तथा आवास के मुख्य द्वार और दीवार को स्प्रे पेंट से ‘गद्दार ज्ञानेश’ लिख दिया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस और पार्टी से संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे, जो बड़ी संख्या में कुमार के विजय नगर स्थित आवास के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने घर की चारदीवारी पर स्टिकर लगाए और पर्चे चिपकाए। प्रदर्शनकारियों ने घर के मुख्य द्वार और दीवार पर ‘ज्ञानेश गद्दार’ और ‘ज्ञानेश चोर’ लिख दिया। प्रदर्शन, और दीवार

पर लिखे गए नारों के वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। भारतीय युवा कांग्रेस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘गद्दार ज्ञानेश’ के घर को कालिख से पोत दिया। पिछले कई वर्षों में मोदी-शाह ने ज्ञानेश के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह चुनावों में गड़बड़ी की है, वह सीधे तौर पर देश के खिलाफ गद्दारी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि ज्ञानेश को सजा मिले। विदित हो कि केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी कुमार ने पिछले साल 19 फरवरी को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था।

जिंदगी ने ज्ञानू को विनम्र बना दिया’-सीईसी पर कॉंकरोच जनता पार्टी का तंज

नई दिल्ली ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद के बीच कॉंकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने चुनाव आयोग पर अपनी राजनीतिक आलोचना तेज की है।

पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने पोस्ट के जरिए ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधकर आरोप लगाया कि उनके कार्य करने के तरीके में अहंकार और निरंकुशता दिखाई देती है। दास ने दावा किया कि युवाओं की ओर से चुनाव आयोग की जवाबदेही का सवाल उठाया जाता रहेगा। दास ने ज्ञानेश कुमार को ‘ज्ञानू’ संबोधित कर कहा कि परिस्थितियों ने उन्हें जमीन पर ला दिया है। उन्होंने

मेरठ और वाराणसी में प्रस्तावित युवाओं तथा जेन-जी के साथ संवाद कार्यक्रमों के स्थगित होने का उल्लेख किया। रिपोर्टों के अनुसार, इन कार्यक्रमों को बाद में प्रशासनिक और लॉजिस्टिक कारणों से स्थगित बताया गया। सीजेपी नेता ने चुनाव आयोग की जवाबदेही के मुद्दे को केवल अदालतों तक सीमित रखने पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर जनता की मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर को लेकर चल रही कानूनी कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा दीं।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला

पाकिस्तान के बेतूके सवाल: भारत के सटीक जबाव

(लेखक- तलित गर्ग)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर वही पुराने सवाल सामने आए, जिनका समाधान दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वां अधिवेशन 8 सितंबर 2026 से शुरू हुआ और इसकी सामान्य बहस 22 से 26 सितंबर के बीच हुई। इस वर्ष की बहस का घोषित केंद्रीय विषय था-विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना और ऐसी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था बनाना जो सभी के लिए प्रभावी हो। ऐसे समय में जब दुनिया युद्धों, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है, यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण एशिया कब पुराने विवादों के चक्र से बाहर निकलेगा।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 26 सितंबर को महासभा में सटीक, तीक्ष्ण एवं प्रभावी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक ‘सीरियल प्रोवित्शनर ऑफ़ टेररिज्म’ ने एक दिन पहले तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया और आतंकवाद को सामान्य बनाने तथा उसके परिणामों से बचने का प्रयास किया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सरकारों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को उजागर करने और उन पर कार्रवाई की आवश्यकता भी रेखांकित किया। इसके एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के निर्णय की आलोचना की। पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जबकि भारत की ओर से पाकिस्तान के सीमा-पार आतंकवाद संबंधी रुख पर सवाल उठाए गए। पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने भी भारत पर आतंकवाद और कश्मीर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का मंच एक बार फिर दोनों देशों के पारस्परिक आरोप-प्रत्यारोप का साक्षी बना। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन आरोपों के बाद भी समाधान की दिशा में कितना रास्ता तय हुआ?

पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आतंकवाद को लेकर उसकी नीति का है। भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से या उसके संरक्षण में सक्रिय आतंकी नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जयशंकर ने इसी संदर्भ में कहा कि आतंकवाद और मित्रता साथ-साथ नहीं चल सकते और आतंकवाद के कर्ता को अपना रास्ता बदलना होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान भारत पर भी आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाता है और अपने यहां होने वाली हिंसक घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। इन परस्पर आरोपों की सच्चाई और प्रमाण अलग-अलग मामलों में जांच का विषय हो सकते हैं, लेकिन इतना निर्विवाद है कि पाक आतंकवाद को पोषित कर भारत की शांति का भंग

करता रहा है, इन आतंकी घटनाओं ने दोनों देशों की जनता को भारी मानवीय, आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। तो फिर सवाल उठता है-पाकिस्तान आखिर कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र की स्थायी विदेश नीति नहीं बन सकता? आतंकवाद यदि किसी देश के लिए रणनीतिक साधन बनाता है तो अंततः वही साधन उस देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता के लिए भी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान स्वयं लंबे समय से आतंकवादी हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में उसके सामने यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह आतंकवाद के प्रश्न को केवल भारत-विरोधी दृष्टिकोण से न देखकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के संदर्भ में भी देखे। आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई केवल किसी दूसरे देश की मांग पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न कश्मीर का है। पाकिस्तान ने इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन लगभग आठ दशक से चली आ रही इस बहस ने यह साबित कर दिया है कि केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान देने से समस्या का समाधान नहीं होता। कश्मीर के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ता है, सुरक्षा तनाव पैदा होता है और दोनों देशों की विकास प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है, तो उसे यह विचार करना होगा कि कश्मीर को अपनी विदेश नीति के स्थायी केंद्र में रखकर वह अपने नागरिकों के भविष्य के लिए क्या हासिल कर रहा है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का उल्लेख करना और घरेलू समस्याओं को पीछे छोड़ देना किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। तीसरा और शायद सबसे गंभीर प्रश्न पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और वहां के आम नागरिक की जिंदगी का है। महंगाई, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे किसी भी सरकार के लिए मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। विदेश नीति तभी सार्थक होती है जब उसका अंतिम उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना हो। पाकिस्तान के लिए यह समय इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ राजनीतिक और कूटनीतिक अभियान चलाने की तुलना में उसकी जनता की आर्थिक आवश्यकताओं, संस्थागत स्थिरता और मानव विकास पर अधिक ऊर्जा लगाना कितना आवश्यक है।

यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत-पाक संबंधों को केवल आरोप-प्रत्यारोप के चश्मे से न देखा जाए। भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और किसी भी



सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के विरुद्ध शून्य-सहिष्णुता की बात कही। लेकिन इसी के साथ क्षेत्रीय शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता और संवाद की संभावनाओं के बीच संतुलन खोजा जाए। संवाद तभी सार्थक हो सकता है जब हिंसा और आतंकवाद के प्रश्न पर स्पष्टता हो। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि दुनिया आज केवल बयान नहीं सुनती, बल्कि नीतियों और व्यवहार को भी देखती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मूल उद्देश्य ही बहुपक्षीय संवाद, शांति और सहयोग के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। यदि इस मंच का इस्तेमाल एक-दूसरे के विरुद्ध आरोपों को दोहराने में ही होता रहे, तो दोनों देशों के नागरिकों को उससे क्या हासिल होगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी हैं। इसलिए इनके बीच तनाव केवल द्विपक्षीय समस्या नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है।

आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा आत्ममंथन यही होना चाहिए कि वह अपने भविष्य को किस आधार पर निर्मित करना चाहता है-पुराने विवादों, कश्मीर-केंद्रित राजनीति और आतंकवाद के आरोपों के आधार पर या आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार, संस्थागत मजबूती और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर? भारत के सामने भी चुनौती यही है कि सुरक्षा से समझौता किए बिना दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की संभावनाओं को खुला रखा जाए। पाकिस्तान कब बदलेगा, इसका उत्तर कोई दूसरा देश नहीं दे सकता। परिवर्तन अंततः पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत निर्णयों और नीति-निर्माताओं पर निर्भर करेगा। लेकिन दिशा स्पष्ट है-आतंकवाद को किसी भी रूप में राजनीतिक साधन न बनने देना, अपनी जनता की आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, कश्मीर के नाम पर लगातार टकराव की नीति से आगे बढ़ना और पड़ोसियों के साथ संबंधों को हिंसा के बजाय विश्वास तथा पारस्परिक सम्मान के आधार पर विकसित करना। यदि पाकिस्तान यह रास्ता चुनता है तो उसका लाभ केवल भारत को नहीं, स्वयं पाकिस्तान के नागरिकों और पूरे दक्षिण एशिया को मिलेगा। और यदि वह पुराने रास्ते पर ही चलता रहा, तो सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया से अधिक उसके अपने नागरिकों के सामने खड़ा होगा-आखिर कब तक अतीत की राजनीति भविष्य की पीढ़ियों का वर्तमान तय करती रहेगी?

(यह लेखक के व्यक्तित्वगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं विदेशी मुद्रा बचाने की अपील

(लेखक- प्रहलाद सबनानी)

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार पुनः भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आवश्यक नहीं हो तो सोना नहीं खरीदे अथवा कम मात्रा में खरीदें। साथ ही आपने यह भी अपील की है कि विदेशी पर्यटन को टालने का प्रयास करें एवं विदेश में जाकर शादी ब्याह के कार्यक्रम नहीं करें। यह समय की मांग है कि भारतीय नागरिक विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से स्वदेशी मंत्र को अपनार्यें।

माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के नागरिकों से उक्त आग्रह इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर परिस्थियां लगातार बिगड़ रही हैं। भारत चुकि आर्थिक विकास के उस चक्र में आ गया है जहां छोटी सी चूक भी भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इस कठिन दौर में भारत को बहुत संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रूस यूक्रेन युद्ध लम्बे समय से लगातार चल रहा है, इजराइल हम्मास युद्ध जारी ही था कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया। उधर, अमेरिका में ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के साथ ही विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की तलवार लगातार लटक रही है। वैश्विक स्तर पर इन विपरीत परिस्थितियों के बीच कई देशों के विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अन्य देशों से आयात करता है। इसी प्रकार, भारत देश में स्वर्ण की कुल मांग का भी 90 प्रतिशत से अधिक भाग आयात करता है। विशेष रूप से, अमेरिका ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कच्चे तेल की आपूर्ति लगभग ठप्प पड़ गई है। भारत में होने वाले कच्चे तेल की कुल आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से आता है। अतः भारत पर उक्त वर्णित

परिस्थितियों का विशेष प्रभाव हुआ है। पिछले वर्ष भारत द्वारा 7,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का स्वर्ण आयात किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में यह 32 प्रतिशत अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण की कीमतों में हुए तेज उछाल के चलते ही भारत के स्वर्ण आयात के बिल में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है अन्यथा स्वर्ण आयात की मात्रा में कुछ कमी ही दर्ज हुई है। भारत के कुल आयात में कच्चे तेल के आयात की भागीदारी सबसे अधिक है, इसके बाद स्वर्ण के आयात की भागीदारी रहती है। इसके चलते भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे, यदि समय रहते नहीं सम्भाला गया तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव आने लगेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूपए की कीमत और अधिक नीचे आने लगेगी।

दूसरे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से कई देशों में मुद्रा स्फीति की दर लगातार बढ़ रही है एवं इसके कारण एवं ब्याज दरों में वृद्धि के चलते इन देशों में बांड यील्ड भी लगातार बढ़ रही है। आज, विभिन्न देशों में बांड यील्ड पिछले कई वर्षों के उच्च स्तर पर आ गई है। जैसे, अमेरिका में 10 वर्षीय बांड यील्ड 4.80 प्रतिशत के उच्च स्तर से भी ऊपर पहुंच गई है, ब्रिटेन में 5.25 प्रतिशत (पिछले 18 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है), फ्रान्स में 4.24 प्रतिशत (पिछले 17 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है), जर्मनी में 3.37 प्रतिशत (पिछले 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है), जापान में 2.99 प्रतिशत जहां पर शून्य प्रतिशत हुआ करती थी (पिछले 30 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है), कनाडा में 3.75 प्रतिशत, ब्राजील में 14.56 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 5.23 प्रतिशत, सिंगापुर में 2.40 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 4.41 प्रतिशत एवं भारत में 6.98 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यदि विकसित देशों में यदि मुद्रा स्फीति की दर और अधिक बढ़ती है तो इसे

नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से ब्याज की दरों को बढ़ाया जा सकता है इससे इन देशों में बांड यील्ड और अधिक बढ़े गी, जिसके चलते भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी मुद्रा में किए गए निवेश की निकासी होगी और यह राशि विकसित देशों में हस्तांतरित होगी क्योंकि इन देशों में बांड यील्ड आकर्षक स्तर पर पहुंच गई है। इन परिस्थितियों के बीच यदि भारत से भी विदेशी मुद्रा निवेश की निकासी प्रारम्भ होती है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव आएगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूपए के मूल्य में तेज गिरावट दृष्टिगोचर होगी जिससे भारत में आयात और अधिक महंगे होने लगेगे, इस प्रकार भारत में आयातित महंगाई की अतिरिक्त मार पड़ेगी। इस बढ़ी हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारत को भी मजबूर होकर ब्याज दरों में वृद्धि करना होगी। ब्याज दरों में वृद्धि का विपरीत प्रभाव देश की सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले बांड पर अदा की जाने वाली ब्याज की राशि पर से और अधिक राशि के भुगतान के लिए भारत को भी मजबूर करेगा है। विकसित देश आज इस समस्या से झूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को इस दबाव से बचाने की आवश्यकता है।

तीसरे, भारत के पास आज 75,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। जापान के पास 1.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं चीन के पास 3.4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है। भारत अपने विदेशी मुद्रा

भंडार को एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाना चाहता है क्योंकि इससे भारत को भविष्य में विदेशी व्यापार में होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाया जा सकेगा। यह तभी सम्भव हो सकेगा, जब भारतीय नागरिक विदेशी मुद्रा का सोच समझकर उपयोग करें। स्वर्ण की खरीद से, विदेश में पर्यटन करने से एवं विदेश में शादियों के कार्यक्रम आयोजित करने से विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ता है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कम होते हैं।

चौथे, भारतीय नागरिकों में स्वर्ण के प्रति आकर्षण कुछ अधिक मात्रा में ही है। यह सही है कि स्वर्ण भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता हुआ दिखाई देता है परंतु देश के विकास की दृष्टि से यह सुप्त मुद्रा के रूप में ही देखा जाता है। स्वर्ण में किए गए निवेश पर किसी भी प्रकार की आय का अर्जन नहीं होता है क्योंकि स्वर्ण में निवेश की गई राशि उत्पादक निवेश की श्रेणी में नहीं गिनी जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारतीय परिवारों के पास लगभग 125,000 टन से अधिक का स्वर्ण भंडार मौजूद है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 125 प्रतिशत है। इतनी भारी भरकम राशि का निवेश निष्क्रिय एवं अनुत्पादक अस्तित्वों में होने के चलते लाखों करोड़ रूपए की राशि पर किसी प्रकार की आय का अर्जन नहीं हो रहा है। यदि इसी निवेश को उत्पादक कार्यों में लगाया जाय तो देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अतः भारत में यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि निवेश को अनुत्पादक अस्तित्वों में घटा कर उत्पादक अस्तित्वों में लगाया जाय।

अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उक्त वर्णित विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय

हरियाणवी प्रतिभाओं को संबल

हरियाणा सरकार के उस फैसले का स्वागत ही किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार ने राज्य में नई खोजों को प्रोत्साहन देने के लिये पचास हजार रुपये तक की, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय किया है। निश्चय ही इस कदम से उन छात्रों को संबल मिलेगा जो सीमित संसाधनों में राज्य व देश के लिये कुछ महत्वपूर्ण खोज करने का संकल्प रखते हैं। लेकिन पेटेंट तो महज एक शुरुआत भर है। असली मुश्किल सवाल यह है कि पेटेंट सर्टिफिकेट मिलने पर मेधावी युवा क्या करेंगे। निर्विवाद रूप से भारत में प्रतिभावान छात्रों, रिसर्च पेपर्स या पेटेंट की कोई कमी नहीं है। दरअसल, कमी है तो उस इकोसिस्टम की जो किसी विचार या आइडिया को लैब या विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट से निकालकर व्यावसायिक दृष्टि से सफल उत्पाद बनाता है। यही वजह है कि छात्रों को पेटेंट के लिये पैसे देने में मदद करने वाली नीति के साथ-साथ प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, बौद्धिक संपदा संरक्षण और नये विचार को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलनी चाहिए। अन्यथा खोज व अनुसंधान अर्थव्यवस्था के महज पेटेंट कल्चर तक ही सिमट जाने का खतरा पैदा हो सकता है। जिसमें समाधान खोजने के बजाय पेटेंट फाइल करने पर इनाम दिया जाता है। सही मायने में इसके लिये कारगर समाधान तलाशने हेतु विश्वविद्यालयों को उद्योग जगत से और करीब से जोड़ने की जरूरत है। छात्रों को वास्तविक दुनिया का समस्याओं की पहचान करने,कंपनियों और सरकार की संस्थानों के साथ काम करने और ऐसे उत्पाद बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनके लिये चिन्हित उपयोगकर्ता की पहले से पहचान हो सके। सही मायने में राज्य में शोध-अनुसंधान का वातावरण बनाने के लिये तमाम व्यावहारिक पक्षों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। नई खोज करने वाले प्रतिभागियों को वित्तीय मदद, उत्पादन के लिये उपयोगी ढांचा, रेगुलेशन और मार्केटिंग से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद की जानी चाहिए। हरियाणा के लिये यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान खेती से जुड़ी विभिन्न तकनीकों, जल प्रबंधन, उत्पादन, हेल्थकेयर और स्वच्छ ऊर्जा आदि अन्य क्षेत्रों में इन्वोवेशन के इंजन बन सकते हैं। इसके लिये सिर्फ एक बार प्रोत्साहन राशि देने के बजाय लगातार निवेश करने की जरूरत होगी। राज्य को अपनी पेटेंट पॉलिसी की सफलता को सिर्फ पेटेंट की फीस की प्रतिपूर्ति वाले आवेदनों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से अपनी सफलता का मूल्यांकन करना चाहिए कि उन पेटेंटों से व्यवहार में क्या हासिल हुआ। मसलन राज्य में कितने स्टार्ट-अप बने। राज्य में कितनी टेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण हुआ। उससे राज्य में नौकरियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि पेटेंट किसी विचार या खोज को सुरक्षा देता है। लेकिन वह इस बात की गारंटी कदापि नहीं है कि व्यवहार में उसका उपयोग राज्य व देश के लिये कितना लाभदायक होगा। यही वजह है कि हरियाणा को व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं के समाधान करने वाले उद्यमों और उत्पाद बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।



हाथी में बैठी भाजपा पर विपक्षी दलों का हमला

(लेखक- सनत जैन)

- भाजपा के लिए ज्ञानेश कुमार बने शनि?

पिछले एक दशक से केंद्रीय चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाते रहे हैं। 2021 के बाद से चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली राजीव कुमार के समय से विवादित हो गई थी राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। इन्होंने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पूरी तरह से बदल दी। मतदाताओं को जोड़ने के स्थान पर कांटना शुरू कर दिया। 15 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा पुराने मतदाताओं को घुसपैठिया बताकर मतदाता सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं 18 साल की उम्र पूरी कर चुके मतदाताओं को मतदाता सूची में नहीं जोड़ा। फार्म 6 में परिवर्तन कर दिया गया। एसआईआर में तार्किक विसंगति के नाम पर विभिन्न राज्यों में नए-नए नियम कानून बनाए गए, नया पोर्टल तैयार किया गया। धरम से जो सॉफ्टवेयर तैयार किए गए उसकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई। राजीव कुमार के टाइम से प्लोटिंग मतदाताओं का जो खेल महाराष्ट्र और

हरियाणा में खेला गया था। वह राजीव कुमार की अती थी। ज्ञानेश कुमार ने इस लाइन को आगे बढ़ाया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बीएलओ के अधिकार केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने पास रख लिए। फार्म 6 और फार्म 7 के जरिए मतदाता सूची में तरह-तरह के फेर बदल करके नाम जोड़ने और काटने का काम किया। यह सब काम इतने गोपनीय तरीके से हुआ, विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने नहीं सुना, इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग में जो गड़बड़ियां हो रही थी। पूरा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के आदेश पर संचालित हो रहा था। दो चुनाव आयुक्तों को भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। जिसके कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत हुई, और एक-एक करके सारे राज खुलते चले गए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस चकव्यूह में बुरी तरह से फिर गए हैं। चुनाव आयोग की सारी गड़बड़ी का लाभ, एक ही राजनीतिक दल को मिला है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है? भारतीय ज्योतिष में जब कर्म फल का समय

खराब आता है। उस समय शनि-राहु और केतु न्याय करने के लिए आगे आते हैं। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। वह बिना किसी भेदभाव के न्याय करते हैं। उनके साथ ग्रह दशा में राहु केतु भी रहते हैं, जो दंड देने का काम करते हैं। सोच को बदलने के लिए अन्य ग्रह भी समय-समय पर शनि के निर्देश पर काम करते हैं। यह ज्योतिषियों की मान्यता है। अगरस्त माह से चुनाव आयोग और भाजपा की ग्रह दशा बदलना शुरू हुई है। इसका असर केंद्र सरकार और भाजपा पर पड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। शनि की महादशा में भारतीय जनता पार्टी हाथी की सवारी करते हुए सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई थी। अब उसी भाजपा पर कांग्रेस ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कॉंग्रेसव पार्टी भी जुड़ गई है। उसने 2 अक्टूबर से मुंबई से आंदोलन शुरू करने की बात कही है। 30 तारीख को सारे विपक्षी दल दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी विश्व कर रहा हैं। एकापक यह दशा ऐसी बदलेगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहावत है, हाथी और ऊंट

में बैठे हुए व्यक्ति को भी जब समय खराब आता है, तो कूटा आकर काट लेता है। कुछ यही स्थिति अब भाजपा और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देखने को मिल रही है। न्यायपालिका जो अभी तक सरकार को संरक्षण दे रही थी। ऐसा न्याय पालिका के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है समय ने अपना न्याय करना शुरू कर दिया है। न्यायपालिका की सोच भी बदल रही है। शनि महाराज जब न्याय की भूमिका में आते हैं, तो न्याय को किसी तरह से टाला नहीं जा सकता है। कर्म का फल देने के लिए ही वह अस्तित्व में आते हैं। पिछले 5-6 सालों से केंद्रीय चुनाव आयोग की सहायता से चुनाव पर प्रभावित करने के लिए मतदाता सूची, मतदान और मतगणना को प्रभावित करने का जो काम हो रहा था। अब वह सब सामने आ चुका है। चुनाव आयोग में बैठे दो चुनाव आयुक्त की नाराजी ने इस सारे खेल को बिगाड़ दिया है। जिस तरह से विभीषण नाराजी, रावण के लिए काल बनी थी। वही स्थिति ज्योतिषियों के अनुसार वर्तमान ग्रह दशा है। 2 अक्टूबर के बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन होने की

तैयारियां चरम पर हैं। 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए थे, वह भी अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आ सकते हैं। इसको लेकर बड़ी चिंता सर्वत्र देखने को मिल रही है। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी अंदाना नक्ये लगा पा रहे हैं, आगे क्या हो सकता है। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। आर्थिक स्थिति केंद्र और राज्यों की गड़बड़ रही है। कर्ज और महंगाई बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार में पिछले 2 महीने से लगातार गिरावट बनी हुई है। आज भी 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट शेयर बाजार में हुई है। हर तरह से सरकार और भाजपा को चुनौती मिल रही है। तब यह कहावत याद आती है, जब मुरीबत आती है, तो वारों तरफ से आती है। जब अच्छे दिन आते हैं, तो भगवान छप्पर फाड़ कर भी धन की वर्षा करता है। भारत में जिस तरह की हालात देखने को मिल रहे हैं। उसमें हर जगह पर चिंता ही चिंता बनी हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास: तोड़ा अपना ही वनडे सीरीज जीत का रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के पहले दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और इस जीत के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे सीरीज जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दक्षिण अफ्रीका की कंगारूओं के खिलाफ रिकॉर्ड 10वें वनडे सीरीज जीत है, जिसमें केवल वे ही देश शामिल हैं जिन्होंने तीन या उससे अधिक मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली है। इस उपलब्धि के साथ, दक्षिण अफ्रीका 10 वनडे सीरीज जीतने वाला पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऑस्ट्रेलिया के

खिलाफ यह कारनामा किया है।

इस विशिष्ट सूची में, दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई कुल 16 सीरीज में से 10 में जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 सीरीज खेली हैं और उनमें से 8 में जीत दर्ज की है। वहीं, भारत इस सूची में तीसरे नंबर पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 15 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिनमें से भारतीय टीम को 6 बार जीत मिली है। पाकिस्तान 12 सीरीज खेलकर 5 जीत के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खेली है। इस उपलब्धि के साथ, दक्षिण अफ्रीका 8 सीरीज खेली हैं और 4 में सफलता प्राप्त की है।

रिकॉर्ड बनाने वाली इस सीरीज के दूसरे मैच

में, दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 365 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर और कसान तेम्बा बाबुमा दोनों ने शानदार शतक जड़े, जिससे टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इसके जवाब में, ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 49.5 ओवर में 333 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने 32 रनों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की, जिसने उन्हें सीरीज में अजेय बढ़त दिलाई और यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने में मदद की। यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाती है।



लवलीना ने बॉक्सिंग में भारत का चौथा पदक पक्का किया, सेमीफाइनल में प्रवेश



निशियो (एजेंसी)। भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरोगेहन ने एशियन गेम्स 2026 में सोमवार को महिला 75 किग्रा वर्ग में अपना दूसरा एशियाई खेल पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने निशियो जिम्नोजियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोरिया की सियोंग सुयोन को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पिछले एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता लवलीना ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती दौर से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ बना ली थी। दोनों खिलाड़ियों ने मुकाबले की शुरुआत रक्षात्मक अंदाज में की, लेकिन भारतीय बॉक्सर ने अपनी पहुंच का फायदा उठाते हुए कुछ सटीक पंच लगाए और पहला राउंड 5-0 से अपने नाम कर लिया। लवलीना बोरोगेहन ने अपने लंबे कद और प्रभावशाली रणनीतिक क्षमता प्रदर्शित करते हुए दूसरे राउंड में भी दबदबा बनाए रखा। उन्होंने फाइनल काउंटर पंच और जैब फेंसले से हराया था।

से जीत गई। आखिरी राउंड में भी भारतीय बॉक्सर ने अपनी लय बनाए रखी और एशियन गेम्स 2010 की कांस्य पदक विजेता पर जबरदस्त प्रहार किए, जिससे उन्हें यह राउंड भी 5-0 से जीतने में सफलता मिली। सभी जजों ने लवलीना के पक्ष में 30-27 का स्कोर दिया, जो उनकी एकतरफा जीत का प्रमाण था। यह पदक मौजूदा एशियन गेम्स में मुक़ेबाजी में भारत के लिए पक्का होने वाला चौथा पदक है। इससे पहले, नरेंद्र बेरवाल ने पुरुषों के +90 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अथापोंग सेंगेटेय को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए देश के लिए तीसरा पदक पक्का किया था। उससे भी पहले, अंकुश पांघल और परवीन हड्डा भी अपनी-अपनी कैटेगरी में पदक सुनिश्चित कर चुके थे। मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन अंकुश पांघल ने पुरुषों के 80 किग्रा क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेक़ुज सलिमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया था।

महिला एकदिवसीय में सबसे बड़ी पारी खेलने वालों में भारत की दीप्ति भी शामिल, शीर्ष पर है एमेलिया केर



नई दिल्ली। महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली शीर्ष दस बल्लेबाजों में भारत की दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। इस सूची में न्यूजीलैंड की एमेलिया केर सबसे आगे हैं। ये खिलाड़ी अपनी इन पारियों से न केवल मेच विजेता रही हैं, बल्कि इन्होंने महिला क्रिकेट के मानकों को भी ऊंचा उठाया है। एमेलिया ने साल 2018 में डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ नाबंद 232 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अपनी 145 गेंदों की इस पारी में इस बल्लेबाज ने 31 चौके और दो छक्के लगाए। करीब 195 मिनट तक बल्लेबाजी कर एमेलिया ने 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। यह महिला एकदिवसीय क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।

एमेलिया से पहले, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा वलार्क ने साल 1997 में मुंबई में डेनमार्क के खिलाफ 115 गेंदों पर नाबंद 229 रन बनाकर महिला एकदिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनने की उपलब्धि अपने नाम की थी। वलार्क ने अपनी पारी में 22 चौके लगाए और 181 मिनट तक बल्लेबाजी की। वहीं श्रीलंका की कसान चमारी अटापट्टु ने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पोंचेफस्ट्रूम में नाबंद 195 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने मात्र 139 गेंदों का सामना करते हुए 26 चौके और पांच छक्के जड़े। 1140.28 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी इस पारी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को यादगार जीत दिलाई।

भारतीय शतरंज टीम ने ओलंपियाड में रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने 46वें चेंस ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को गौरव दिलाया है। पुरुष टीम ने प्रतिष्ठित सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि महिला टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को हार्दिक बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनका जुनून और दृढ़ संकल्प मिसाल कायम करने वाला है। उम्मीद है कि ये सफलताएं और भी कई युवाओं को शतरंज खेलने और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी।

अंतिम राउंड के रोमांचक मुकाबलों के बाद भारतीय पुरुष ओपन टीम ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। भारत ने हंगरी के खिलाफ 2-2 से

मुकाबला ड्रॉ खेला। इस महत्वपूर्ण मैच में, मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश को रलेब डुडिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन एर्रिसी ने पीटर लेको को हराकर भारत को बराबरी दिलाई और सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया। पुरुष वर्ग में मेजबान उज्बेकिस्तान ने आखिरी राउंड में यूक्रेन को 2.5-1.5 से हराकर गोल्ड मेडल जीता, मुखिबेदीन मदामिनोव ने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उज्बेकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को दो अंक आगे रहते हुए अपना दूसरा शतरंज ओलंपियाड खिताब जीता। भारत ने टाई-ब्रेक के आधार पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जबकि जर्मनी ने नीदरलैंड्स को 2.5-1.5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसमें मैथियास व्लुबाउम की जीत निर्णायक रही।

महिला वर्ग में, भारतीय टीम ने जॉर्जिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर पोंडियम पर अपनी

जगह पक्की की। सविता श्री ने दबाव में मेरी अराबिदुजे के खिलाफ ड्रॉ खेलकर टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, जिससे भारत तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहा। महिला वर्ग का गोल्ड मेडल चीन ने विजयनाम को 3-1 से हराकर जीता, वहीं कजाकिस्तान ने पोलैंड के खिलाफ 2-2 की बराबरी के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। चीन ने दो अंकों की बढ़त के साथ अपना सातवां महिला शतरंज ओलंपियाड खिताब जीता। भारत ने टाई-ब्रेक के नियमों के तहत अमेरिका, पोलैंड, ऑर्मेनिया और मोंगोलिया जैसी मजबूत टीमों को पीछे छोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रकार, भारतीय दल ने टूर्नामेंट का समापन एक अविस्मरणीय प्रदर्शन के साथ किया, जहां पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शीर्ष तीन में जगह बनाकर देश को दोहरा पोंडियम फिनिश दिलाकर गौरवान्वित किया।



कुराश में पिंग्की बल्हारा ने जीता कांस्य, सेमीफाइनल में मिली हार

नगोया (एजेंसी)। भारत की पिंग्की बल्हारा ने सोमवार को एशियन गेम्स 2026 में कुराश के -78 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि, उन्हें स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह बनाने से चूकना पड़ा, क्योंकि सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली पिंग्की बल्हारा को एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल मैच में साउथ कोरिया की मो सुमिन से 0-5 से शिकस्त मिली। सेमीफाइनल में मो सुमिन का पिंग्की के खिलाफ पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ी को एक डक्की (कुराश में दो चेतावनी) मिली, जबकि सुमिन ने पहले आधा प्लांट चाला और बाद में योनबोश (पूरा प्लांट) हासिल करके मुकाबला 5-0 से जीत लिया। पिंग्की बल्हारा ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में एक और साउथ कोरियाई खिलाड़ी लिम को 3-0 से हराया था। उस मुकाबले में उन्होंने कोरियाई खिलाड़ी के



खिलाफ चाला (आधा प्लांट) हासिल किया था, जबकि लिम को तानबेख (चेतावनी) मिली थी। पिंग्की ने एशियन गेम्स 2018 में रजत पदक जीता था, जब इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट में कुराश को पहली बार शामिल किया गया था। वह पहले जुझे खिलाड़ी थीं और उन्होंने एशियाई जूनियर जुझे चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक भी जीता था। हालांकि,

वह जुझे इवेंट में भारत की एशियन गेम्स की टीम में जगह नहीं बना पाई थीं, लेकिन बाद में पिंग्की ने कुराश इवेंट के लिए क्वालीफाई किया और अपना अनुभव धुनाते हुए रजत पदक जीता।

मौजूदा एशियन गेम्स में कुराश मुकाबलों में भारत को पिंग्की बल्हारा के रूप में यह पहली सफलता मिली है। रविवार को भारतीय

खिलाड़ी एक भी मैच नहीं जीत पाए थे, जो टीम के लिए निराशाजनक था। पुरुषों के 90 प्लस किग्रा वर्ग में विशाल का सफर क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया, जब उन्हें थाईलैंड के कुनाथिय थे-ऑन के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी संगीता बल्हारा महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर सकीं। उन्हें राउंड ऑफ 32 में फिलीपींस की चारमिया क्रेलिनो के खिलाफ 0-10 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारतीय भी प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। उन्हें ईरान की ताहरेह अजरपेइवद ने हराया। वहीं, पुरुषों के 90 प्लस किग्रा वर्ग में यश कुमार चौहान का सफर भी राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया, जब उन्हें ताजिकिस्तान के शकरममद मिस्ममदेव के खिलाफ 0-10 से हार मिली। पिंग्की का कांस्य पदक भारतीय टीम के लिए एक राहत और प्रेरणा लेकर आया है।

तेज बारिश ने रोका मैच, हॉन्गाकॉन्ग से खेले बगैर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा

टोवयो। आइवी-नागोया एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट में पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच खेला जाने वाला पहला क्वार्टर फाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में लगातार बारिश के चलते मैदान खेलने लायक नहीं था, जिसके कारण मैच नहीं हो सका और एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। मुकाबला रद्द होने का फायदा पाकिस्तानी टीम को मिला। आइसीसी की टी20 रैंकिंग में बेहतर टीम होने के कारण पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं हॉन्ग कॉन्ग का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल सोमवार को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होना था, जबकि टॉस 5 बजे होना था, लेकिन मैच से पहले ही बारिश तेज हो गई। गंभी आउटफील्ड के कारण मैच शुरू होने की कोई संभावना नहीं बनी। अधिकारियों ने मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल के लिए रिजर्व डे का प्रावधान नहीं था, इसलिए बेहतर रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान को फायदा हो गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बाकी क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद होगा। एशियन गेम्स 2026 के दोनों सेमीफाइनल गुरुवार 1 अक्टूबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली थी। बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को नोकआउट चरण में सीधे प्रवेश दिया गया था। दूसरी और हॉन्ग कॉन्ग ने स्टेज में अच्छे प्रदर्शन के जरिए क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया था। हॉन्ग कॉन्ग की टीम को ग्रुप स्टेज में एकमात्र जीत ओमान के खिलाफ मिली थी।

1159 दिन बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने कुलदीप यादव, पर श्रेय विराट-गिल को दिया



नई दिल्ली (एजेंसी)। विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारियों की बदौलत भारत ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए थे। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी कर्सी हुई और निर्णायक गेंदबाजी के कारण ही वेस्टइंडीज की टीम 300 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सकी, जिसने भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया। कुलदीप यादव के इस प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए मैच खत्म होने के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

हालांकि, टीम इंडिया का यह प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस अवॉर्ड को लेने में थोड़ी झिझक महसूस कर रहा था। कुलदीप ने अवॉर्ड स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यह अवॉर्ड क्यों मिला, जबकि विराट और गिल ने इतनी असाधारण बल्लेबाजी की थी। कुलदीप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ंसच कहूं तो मुझे मैंन ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते हुए थोड़ा अनजान लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से विराट

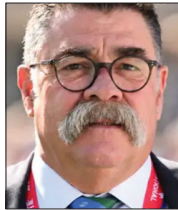
भाई और गिल ने बल्लेबाजी की, वह वाकई शानदार थी। मेरे ख्याल से इसे लेकर फैसला कुछ और भी हो सकता था।:- यह बयान उनकी विनम्रता और टीम के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय है कि कुलदीप यादव को बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें मैदान पर उतारा गया, उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर अपनी उपयोगिता साबित की। यही कारण है कि कुलदीप वनडे में पूरे 1159 दिन बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। कुलदीप इससे पहले 27 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के ही खिलाफ बारबाडोस में 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने 88 गेंदों में 10 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबंद 139 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 108 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल था। विराट और गिल के इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने 41.4 ओवर में ही सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाकर आसानी से मैच जीत लिया। कुलदीप का प्रदर्शन निश्चित रूप से जीत में अहम था, लेकिन बल्लेबाजों ने उन्हें भी हैरान कर दिया।

विराट बोले, ये मेरा अंतिम विश्वकप, टीम को खिताबी जीत दिलाना है लक्ष्य



नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि आगले साल 2027 में होने वाला एकदिवसीय विश्वकप उनके करियर का अंतिम विश्व कप होगा जिसे वह हर हाल में जीतना चाहते हैं। कोहली के अनुसार उनका लक्ष्य विश्वकप में भारतीय टीम को जीत दिलाना है और इसके लिए वह पूरी ताकत लगा देंगे। इसी के साथ ही विराट ने अपने विश्व कप भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर भी अंकुश लगा दिया। अब तक कहा जा रहा था विराट को शायद ही टीम में शामिल किया जाये पर इस बल्लेबाज ने इसमें खेलने की अपनी इच्छा खुलकर जता दी है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह अंतिम विश्व कप है, जिसमें मैं भारत के लिए खेलने जा रहा हूं। मैं अपना सब कुछ मैदान पर छोड़ना चाहता हूं इसलिए मेरा अंतिम लक्ष्य विश्व कप जीतना है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। इससे साफ है कि विराट अपने करियर का समापन विश्व कप की जीत के साथ करना चाहते हैं। इस बल्लेबाज ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। गौरतलब है कि 2027 एकदिवसीय विश्व कप अवटूर और नवंबर में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू पर मुकाबले आयोजित किए जाएंगे हैं। भारत ने अपना पिछला एकदिवसीय विश्व कप खिताब 2011 में जीता था, जिसके बाद 2023 में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताब नहीं जीत पायी थी। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 2019 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां उसे न्यूजीलैंड से हार मिली थी।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को मिला नया अध्यक्ष : विश्व कप विजेता डेविड बून संभालेंगे कमान



नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशासन में एक बड़ा बदलाव आया है, जहाँ बोर्ड ने सोमवार को पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व विश्व कप विजेता क्रिकेटर डेविड बून क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अंतिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। बून ने माइक बेयर्ड का स्थान लिया है, जिन्होंने बिग बैश लीग (बीबीएल) के निजीकरण और उसमें निजी निवेश लाने के विवादस्पद फैसले को लेकर अन्य बोर्ड सदस्यों के भारी दबाव के बाद अपने दल से

इस्तीफा दे दिया था। माइक बेयर्ड के इस कदम का न्यू साउथ वेल्स जैसे प्रमुख राज्यों ने भी कड़ा विरोध किया था, जिसके प्रतिनिधि के रूप में वह बोर्ड में आए थे। डेविड बून ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महान खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 1984 से 1996 तक कंगारू टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने करियर में 107 टेस्ट मैच और 181 वनडे मैच खेले, जिनमें कुल मिलाकर 13,000 से अधिक रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 7422 रन दर्ज हैं, जिसमें 22 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 5 शतक और 37 अर्धशतकों सहित 5964 रन बनाए। बून उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का अभिन्न हिस्सा थे जिसने 1987 में विश्व कप जीता था, जहाँ उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ 75 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी।

